

भारत का वित्तीय क्षेत्र – भावनिकता से समुत्थानशीलता की ओर*

माइकल देवब्रत पात्र

नमस्कार।

जानकारीपरक उद्घाटन टिप्पणियों के लिए धन्यवाद अल्फ्रेडो मैं बताना चाहूंगा कि अल्फ्रेडो ने 2021 परामर्श के लिए आईएमएफ के आर्टिकल IV भारत मिशन का नेतृत्व किया था। उनके व्यापक अनुभव और भारतीय परिस्थितियों की गहरी समझ उनके विचारों में परिलक्षित होती है। मैं अल्फ्रेडो और उनके सह-संपादकों की भी सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने भारत की वित्तीय प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन किया और हाल ही में "इंडियाज फिनान्शियल सिस्टम: बिल्डिंग दी फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एण्ड सस्टेनेबल ग्रोथ" नामक पुस्तक में भविष्य के लिए बहुत मूल्यवान सिफारिशें कीं।

मुझे इस सत्र में आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग से श्री थॉमस हेलब्लिंग को देखकर खुशी हो रही है, और मैं उनसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ।

मैं अपने मेजबान और सीसेन एक्सको के अध्यक्ष, नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया, सीसेन केंद्र (एसईएसीएन) और डॉ मंगल गोस्वामी, कार्यकारी निदेशक और बीआईएस को इस प्रतिष्ठित मंच में बोलने के लिए आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं उप गवर्नर सुम सन्निसिथ का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस 16वें सीसेन-बीआईएस उच्च स्तरीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आत्मीयतापूर्वक पत्र लिखा।

पृष्ठभूमि

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि अगले दो दशकों के दौरान – जो कि लंबा समय नहीं है – वैश्विक अर्थव्यवस्था का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूर्व की ओर एशिया में स्थानांतरित हो जाएगा।

* 18 सितंबर 2023 को सिएम रीप, कंबोडिया में नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया द्वारा आयोजित 16 वें सीसेन-बीआईएस उच्च स्तरीय संगोष्ठी में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उप गवर्नर माइकल देवब्रत पात्रा द्वारा दिया गया भाषण। स्नेहल एस. हेरवाडकर, सोनाली गोयल, आशीष थॉमस जॉर्ज से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियां और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहयोग सराहनीय है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएमएफ के क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य से संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र 2023 में ही वैश्विक संवृद्धि में लगभग दो-तिहाई योगदान देगा। भारत 2023 और 2024 में विश्व उत्पादन वृद्धि का छठा हिस्सा होगा। बाजार विनिमय दरों के मामले में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा अंदाज़ है कि 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा और बाजार विनिमय दरों के हिसाब से भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इस परिवर्तन में एक प्रमुख चालक जनसांख्यिकीय लाभांश का एक घटक होने की संभावना है जो 2018 से देखा जा रहा था और संभवतः प्रजनन और मृत्यु दर के आधार पर 2040 के दशक तक चलेगा। पहले से ही हम 1.4 बिलियन संख्या के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश हैं और 28 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे युवा हैं। भारत की प्रगति का दूसरा प्रमुख उत्प्रेरक वित्तीय क्षेत्र के विकास की गति और गुणवत्ता होगी, जो आज मेरे संबोधन का विषय है। यहां कुछ स्लाइडों की मैं मदद लूंगा (अनुबंध I)।

एशिया के बाकी हिस्सों की तरह एक उच्च बचत दर वाली अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं की संसाधन आवश्यकताओं को जुटाने के लिए एक आधुनिक, कुशल और अच्छी तरह से काम करने वाला वित्तीय क्षेत्र आवश्यक है। इस विषय पर किए गए अध्ययन में व्यापक रूप से यह बात सामने आयी है कि वित्तीय क्षेत्र के विकास का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक गुणक प्रभाव पड़ता है, जिसमें उत्पादकता और आवंटन दक्षता लाभ प्रदान करना शामिल है। हालांकि निर्णायक मंडल अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि आर्थिक प्रगति वित्त आधारित है या उसके क्रम में मांग का अनुसरण कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण अनुभवजन्य साक्ष्य एशिया के विकास पथ को वास्तविक अर्थव्यवस्था के रूप में इंगित करता है जो वित्तीय विकास का नेतृत्व कर रहा है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। इस बात के भी अनुभवजन्य प्रमाण हैं कि एशिया भर में वित्तीय क्षेत्र की संरचना बदल रही है और अब तक की बैंक-वर्चस्व वाली प्रणालियों ने गैर-बैंकों और पूंजी बाजारों जैसे वैकल्पिक वित्तीय मध्यस्थों को जगह दी है। ये विकास, बदले में, अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के लिए संवृद्धि अनुकूल वातावरण उत्पन्न करते हैं।

भारत में, अतिरिक्त आयामों ने हमारी विकास क्षमता का लाभ उठाने के लिए सकारात्मक संभावनाएं पैदा की हैं, जो इस प्रकार हैं – डिजिटल क्रांति; भुगतान और निपटान पारिस्थितिकी तंत्र का परिवर्तन; और वित्तीय समावेशन में नवाचारा हाल ही की बात करें तो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत का तेजी से विस्तार वित्तीय क्षेत्र सहित हमारे जीवन के हर पहलू को नया रूप दे रहा है। इस पृष्ठभूमि में, मैंने सोचा कि मैं भारत के वित्तीय क्षेत्र के कुछ पहलुओं, जैसे कि इसकी आज की स्थिति, वर्षों से हो रहा स्थिर कायापलट, और आगे के रास्ते पर मुख्य चुनौतियां और अवसर को प्रस्तुत करूंगा।

भारत के वित्तीय क्षेत्र की संरचना

व्यापक रूप से देखें तो वित्तीय प्रणाली में गैर-वित्तीय क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले ऋण प्रवाह में बैंकों का 60 प्रतिशत हिस्सा है, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) 8 प्रतिशत ऋण प्रदान करती हैं, वित्तीय बाजार और अन्य का 20 प्रतिशत और विदेशी स्रोत का 12 प्रतिशत का योगदान है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी (दीर्घकालिक पुनर्वित्त संस्थानों, प्राथमिक डीलरों और आवास वित्त कंपनियों सहित) और वित्तीय बाजार क्षेत्र के धन, गिल्ट, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट खंडों के विनियमन, पर्यवेक्षण और विकास के लिए उत्तरदायी है। अपनी शेष टिप्पणियों में मैं वित्तीय क्षेत्र के इन घटकों पर बात करूंगा। एक अंतर-विनियामकीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) है जो पूरी वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखती है और समन्वय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी की एक उप-समिति है।

बैंकिंग क्षेत्र

सबसे पहले, मैं बैंकिंग प्रणाली की ओर मुड़ता हूँ। आमतौर पर, भारत की बैंकिंग प्रणाली को सरसरी तौर पर सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली और भारी सार्वजनिक नीति के हस्तक्षेप के रूप में वर्णित किया जाता है। वास्तव में यह प्रणाली अत्यंत सक्रिय है। इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनकी कड़ी स्पर्धा 21 निजी बैंकों, 45 विदेशी बैंकों और 63 विशिष्ट बैंकों¹ से होती है। यह

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग प्रणाली के सभी घटक एक ही विनियामकीय दायरे में आते हैं, जिसमें विशिष्ट और स्थानीय बैंकों के निधि स्रोतों और उसके उपयोग के संदर्भ में विशिष्ट अंतर हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत ने 1997-98 के एशियाई संकट या 1980 और 2002 के लैटिन अमेरिकी संकट या 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बड़े और गंभीर वित्तीय संकट का सामना नहीं किया है। हालांकि भारत में भी वित्तीय उतार-चढ़ाव हुए, लेकिन उनका स्वरूप स्थानीय प्रकार का अधिक था, और विशेष रूप से वे चक्रीय बदलाव के परिणाम थे।

2001-02 में भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से बाहर आई और आर्थिक उत्थान ने जोर पकड़ा जिससे बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ऋण वृद्धि को बल मिला। तथापि ढीले ऋण मानकों और अपारदर्शी आस्ति गुणवत्ता पहचान के कारण, जीएफसी की शुरुआत के साथ यह बेअसर हो गया। भारत जीएफसी से बाहर निकलने वाले शुरुआती देशों में से एक था। दोहरे अंकों की संवृद्धि आकांक्षाओं ने बैंक ऋण-आधारित बुनियादी ढांचे और भारी उद्योग निवेश को बढ़ावा दिया। इस आधार पर कि बुनियादी ढांचे में लंबी अवधि शामिल है, बैंक ऋणों को पुनर्गठित करने की अनुमति दी गई थी, जबकि उन्हें अपर्याप्त प्रावधान के साथ बैंकों के बही-खातों में मानक अग्रिम के रूप में माना गया था।

2015-16 में एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) के रूप में गंभीर पहल की गई जिससे बैंकों की आस्तियों की सही गुणवत्ता सामने आने लगी। पुनर्गठित ऋणों की उचित पहचान होने से, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और लिवरेज पर सीमा को शामिल करते हुए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा 2017 से उच्च प्रावधानों की आवश्यकता के अलावा ऋण, लाभांश-वितरण और शाखा विस्तार पर प्रतिबंध के साथ लागू किया गया। सबसे पहले 12 बैंकों को इस ढांचे के तहत रखा गया था। 2017-22 के दौरान सरकार द्वारा 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर² राशि का बड़े पैमाने पर पुनर्पूँजीकरण किया गया। यह एक अवांछित पहल थी, लेकिन इसके लाभकारी

¹ इसमें 12 लघु वित्त बैंक, 6 भुगतान बैंक, 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

² भारतीय रुपये में 2.9 लाख करोड़ रुपये।

प्रभाव 2018 से दिखाई देने लगे, जिसके परिणामस्वरूप आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ। सकल गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात, जो मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के शिखर पर था, गिर कर मार्च 2023 तक 3.9 प्रतिशत हो गया। 2022 तक सभी संकटग्रस्त बैंक पीसीए से बाहर हो गए।

हाल के वर्षों में, कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहलों ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया है। दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना से बैंकों के तुलनपत्र दबाव को स्थायी आधार पर दूर करने के लिए संस्थागत माहौल तैयार किया। ऑफ-साइट निगरानी प्रणालियों को सुपटेक - एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ्लो एप्लिकेशन जिसे **दक्ष** कहा जाता है, और केंद्रीकृत सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) नामक एक स्वचालित डेटा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तेज और अधिक व्यापक बनाया गया है। पर्यवेक्षी पहलों के पूरक के रूप में बिग डेटा तकनीकों का लाभ उठाया जा रहा है, जबकि **साइबर रेंज** – जो एक आभासी नियंत्रित वातावरण और उपकरण है - साइबर सिक्युरिटी ड्रिल में मदद करता है। विलय के कारण दक्षता में लाभ हुआ है। विनियामकीय सैंडबॉक्स नवाचार को बढ़ावा देता है। जमाकर्ता सुरक्षा कवच का विस्तार, जमा बीमा का अग्रिम भुगतान और एक छत के नीचे विभिन्न लोकपाल योजनाओं के एकीकरण ने विवाद निवारण तंत्र को सरल और अधिक उत्तरदायी बना दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ रहा है।

बैंकों के तुलनपत्रों पर बोझ न होने की वजह से वे महामारी की मार झेल पाए। हाल ही में ऋण में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पहले के अनुभवों से प्रेरित होकर, हम हाई अलर्ट पर रहते हैं, और अत्यधिक जोखिम लेने के किसी भी संकेत के लिए क्षेत्रगत और संस्थान-विशिष्ट ऋण विस्तार और अंडरराइटिंग मानकों की लगातार निगरानी करते हैं।

2013 से भारत ने बेसल III मानदंडों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की। पूंजी आवश्यकताओं को बेसल III न्यूनतम से एक प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया था, जिसमें सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) भी शामिल था। 2015 में, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) पेश किया गया था; महामारी के दौरान 0.625 प्रतिशत

की अंतिम किस्त को अस्थायी रूप से विलंबित कर दिया था, लेकिन उसे अक्टूबर 2021 में बहाल कर दिया गया था। काउंटर-साइक्लिकल कैपिटल बफर के लिए दिशानिर्देश 2015 में बैंकों को जारी किए गए थे, लेकिन इसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है क्योंकि क्रेडिट गैप नकारात्मक बना हुआ है। 100 प्रतिशत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की आवश्यकता को 2019 में लागू किया गया था और बैंकों ने लगातार इसे न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर बनाए रखा है, जो बेसल III मानदंड भी है। 2021 के बाद से, शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात भी लागू किया गया है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में लगातार सुधार हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप, निवल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात मार्च 2023 तक घटकर 1 प्रतिशत हो गया है।

तुलनपत्र में सुधार और पूंजी तथा चलनिधि बफर के पुनर्निर्माण जैसी कार्रवाई का असर आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ दोनों के संदर्भ में मजबूत सुधार के रूप में लाभप्रदता में परिलक्षित होता है जो 2018 और 2019 के दौरान नकारात्मक थे। मई 2022 से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए मौद्रिक नीति चक्र के रुख को सख्ती की ओर बदलने के साथ, चालू खाता बचत खाता (सीएएसए) जमा दरों की तुलना में उधार दरों में पूर्ण संचरण के कारण बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) का विस्तार हुआ है। यही बात परिस्थितिजन्य मौद्रिक नीति कार्यों की अवधि के दौरान कई उन्नत अर्थव्यवस्था (ईई) बैंकों में देखी गई है। एनआईएम के विस्तार को महामारी से संबंधित उपायों से चलनिधि के प्रवाह से भी मदद मिली है, जिसने बैंकों को आकर्षक दरों की पेशकश करके जमा जुटाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, बैंक ऋण की निगरानी ओवरहीटिंग के प्रमुख संकेतक के रूप में की जाती है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित हमारा आकलन इंगित करता है कि ऋण विस्तार की वर्तमान गति प्रणालीगत दबाव निर्माण की ओर इशारा नहीं कर रही है - भारतीय संदर्भ में 16-18 प्रतिशत की संवृद्धि दर को चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्रेडिट गैप - जो कि ऋण और जीडीपी अनुपात और इसकी प्रवृत्ति के बीच का अंतर है - वर्तमान में नकारात्मक है। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली में एनआईएम औसतन लगभग 3.8

प्रतिशत है, जो 5 प्रतिशत की अनुमानित सीमा से नीचे चल रहा है, जिसके बाद लीवरेज बाधाओं और प्रतिकूल चयन के कारण वित्तीय स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल, शाश्वत सतर्कता वित्तीय स्थिरता की कीमत है।

बैंक ऋण विस्तार की वर्तमान कड़ी में खुदरा ऋण अधिक हैं। पारंपरिक अनुभवों से पता चलता है कि इस प्रकार के ऋण व्यापक उधारकर्ताओं में वितरित होता है जो प्रणालीगत जोखिम के संचय को कम करता है - सभी उधारकर्ता एक साथ चूककर्ता नहीं हो सकते हैं। हालांकि, हम इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि बैंक अगर खुदरा ऋण क्षेत्र में समूहों को ऋण देते हैं और यदि चूक होती है तो प्रणाली को संभावित नुकसान हो सकता है।

ऋण जोखिम के लिए व्यापक दबाव परीक्षण से पता चलता है कि भारत में सभी बैंक गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम होंगे। मार्च, 2024 तक बेसलाइन, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत प्रणाली-स्तरीय पूंजी अनुपात क्रमशः 16.1 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो विनियामकीय न्यूनतम 9 प्रतिशत से काफी ऊपर है। जमाराशियों पर किसी भी संभावित रन-ऑन के प्रभाव का अंदाज़ लगाने के लिए किए गए चलनिधि जोखिम विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 15 प्रतिशत गैर-बीमाकृत जमाओं की अचानक और अप्रत्याशित निकासी के चरम परिदृश्य में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के 75 प्रतिशत अप्रयुक्त हिस्से के उपयोग के साथ, प्रणाली स्तर पर चल आस्ति कुल आस्तियों के 21.1 प्रतिशत से घटकर 11.4 प्रतिशत हो जाएगी। लेकिन यह नकारात्मक स्तर तक नहीं जाएगी। इसके अलावा, बैंकों की ऋण एकाग्रता पर दबाव परीक्षण - उनके मानक एक्सपोजर के अनुसार शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को देखते हुए - से पता चलता है कि शीर्ष तीन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के पुनर्भुगतान करने में विफल रहने के चरम परिदृश्य में भी, किसी भी बैंक को 9 प्रतिशत की विनियामकीय आवश्यकता से नीचे पूंजी अनुपात में गिरावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि दो बैंकों को सीसीबी आवश्यकता (11.5 प्रतिशत) सहित विनियामकीय न्यूनतम से नीचे पूंजी अनुपात में गिरावट दिखाई देगी।

कुछ उन्नत अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्राधिकारों में कुछ बैंकों की हालिया विफलता से पता चलता है कि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि के संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसने उनके तुलनपत्र में स्थित दोष को उजागर किया। ब्याज दरें बढ़ने से उनके होल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) पोर्टफोलियो में अप्राप्त मूल्यांकन नुकसान बढ़ गया, जो मार्क-टू-मार्केट नहीं हैं। अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में कुल मूल्यांकन नुकसान 2021 के अंत में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 के अंत में 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। गैर-बीमित जमाओं के बड़े पोर्टफोलियो ने अप्राप्त मूल्यांकन घाटे के प्रभाव को बढ़ा दिया, जिससे बैंक रन की स्थिति बनी। अपर्याप्त पूंजी की स्थिति ने उनके जोखिम प्रोफाइल को बिगाड़ दिया (चार्ट में, नीले और लाल बिंदुओं के बीच की दूरी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी के क्षरण को दर्शाती है)।

भारतीय संदर्भ में, यदि प्रतिफल वक्र में 250 आधार अंकों के समानांतर ऊपर की ओर बदलाव के रूप में आघात लागू किया जाता है, तो बैंकों के एचटीएम पोर्टफोलियो पर मार्क-टू-मार्केट प्रभाव (अप्राप्त नुकसान को छोड़कर) सिस्टम स्तर पूंजी अनुपात को मार्च 2023 में 17.1 प्रतिशत से घटाकर 13.7 प्रतिशत कर देगा, जो फिर भी विनियामकीय आवश्यकता से ऊपर है।

डिजिटल परिवर्तन

भारत में वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी पर आधारित एक परिवर्तनकारी बदलाव के शिखर पर है। जेएएम त्रिमूर्ति - जन धन (बेसिक नो-फ्रिल खाते); आधार (सार्वभौमिक विशिष्ट पहचान); और मोबाइल कनेक्शन - अब तक वंचित रहे लोगों को औपचारिक वित्त के दायरे में ला रहा है और लाभार्थियों को सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लक्ष्य को सक्षम कर रहा है। वर्तमान में, सर्वोच्च 500 मिलियन जन धन लाभार्थी हैं, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं हैं। मोबाइल इंटरनेट ग्राहक सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे ई-सरकारी सेवाओं के कुशल वितरण के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए अभिनव ई-बिजनेस मॉडल के रास्ते खुल गए हैं। यह तकनीकी स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करके उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), जो एक ओपन-

एंडेड सिस्टम है, किसी भी सहभागी बैंक के एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों के लिए सुविधा देता है। इसके अलावा यह अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर और व्यक्ति-से-व्यापारी निर्बाध लेनदेन की सुविधा देता है। यह भुगतान क्रांति व्यापक अंतरराष्ट्रीय रुचि को आकर्षित कर रही है। अगस्त 2023 में, यूपीआई ने एक महीने में 10 बिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज करने का सर्वोच्च मान दर्ज किया। इसके अलावा, भारत में बड़े मूल्य और छोटे मूल्य, दोनों भुगतान प्रणालियां³ वर्ष के चौबीसों घंटे काम करती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अंतिम छोर तक पहुंच

भारत की वित्तीय प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण खंड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारत के वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण मध्यस्थों के रूप में उभरी हैं क्योंकि वे अंतिम छोर को जोड़ती हैं और बैंकों को एक विकल्प भी प्रदान करती हैं। अन्य क्षेत्राधिकारों के विपरीत, एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों की तरह ही विनियामकीय नियंत्रणों के साथ आकार-आधारित ढांचे में विनियमित किया जाता है। उनकी बढ़ती उपस्थिति 2012-13 और 2021-22 के बीच जीडीपी अनुपात में बढ़ते ऋण अनुपात में परिलक्षित होती है, जो 8.6 प्रतिशत से 12.3 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह क्षेत्र 2018-19 और फिर महामारी के दौरान बाजार का विश्वास खो जाने जैसे चलनिधि दबाव के दौर से गुजरा है। लेकिन यह स्वस्थ और मजबूत होकर उभरा है। इस क्षेत्र में ऋण संवृद्धि दोहरे अंकों में है, मजबूत पूंजी उपलब्धता है और इनके तुलनपत्र स्वस्थ हैं।

एनबीएफसी अपनी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए ऋण पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इनके ऋण में मार्च 2023 के अंत में बैंकों का लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग नब्बे प्रतिशत बैंक ऋण उन एनबीएफसी को दिया जाता है जो ए-रेटेड और उससे ऊपर हैं। इसलिए, संक्रमण जोखिम सीमित है। बेसलाइन और दो तनाव परिदृश्यों - मध्यम और उच्च जोखिम के तहत क्रेडिट जोखिम आघातों के लिए एनबीएफसी क्षेत्र की समुत्थानशीलता का आकलन करने के लिए प्रणाली स्तर के दबाव परीक्षण से पता चलता है कि स्लिपेज अनुपात में एक मानक विचलन (एसडी) वृद्धि के मध्यम जोखिम आघात के तहत,

जीएनपीए अनुपात बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो जाता है। परिणामस्वरूप आय हानि और अतिरिक्त अनंतिम आवश्यकताएं बेसलाइन के सापेक्ष सीआरएआर को 60 आधार अंक कम कर देती हैं। 2 एसडी के उच्च जोखिम आघातों के तहत, क्षेत्र का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसलाइन के सापेक्ष 90 बीपीएस घटकर 23.5 प्रतिशत हो जाता है।

वित्तीय बाजार

जिस तरह एनबीएफसी वित्त के स्रोत के रूप में बैंकों के पूरक हैं, उसी तरह वित्तीय बाजार संसाधन जुटाने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों की अगुवाई में, भारत के इक्विटी बाजार एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएससीआई में भारत की हिस्सेदारी 2012 में 6.5 प्रतिशत थी, जो बढ़कर अगस्त 2023 तक 14.9 प्रतिशत हो गई है, जो उज्ज्वल आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, और उच्च निश्चिष्ट निवेश को आकर्षित करने की उम्मीदों को बढ़ाती है। भारत का 12 महीने का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग (पीई) अनुपात दुनिया में सबसे अधिक है, जो भारत की विकास यात्रा के महत्व को दर्शाता है। भारत में इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव (VIX) काफी हद तक स्थिर रहा है और प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम है। भारत अप्रैल-जुलाई 2023 के दौरान तुलनीय ईएमई के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

बॉन्ड बाजारों में प्रतिफल वक्र सपाट है, लेकिन अन्य देशों की तरह यह विपरीत दिशा में नहीं है, जो भारत की वृद्धि संभावनाओं के साथ-साथ वैश्विक स्पिलओवर से कुछ हद तक बचाव की उम्मीदों को दर्शाता है। भारतीय रुपया दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। 2023 के दौरान (11 सितंबर तक), रुपये की 1 महीने की निहित अस्थिरता जो 2022 में इसी अवधि के दौरान 5.22 प्रतिशत थी, घटकर 4.08 प्रतिशत हो गई। भिन्नता के गुणांक द्वारा मापी जाने वाली आईएनआर अस्थिरता, प्रमुख आई और ईएमई के बीच सबसे कम बनी हुई है। विनिमय दर स्थिरता को वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।

³ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण एक नए प्रतिमान को प्रतिबिंबित कर रहा है जिसमें व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को दृढ़ता से पूरक के रूप में देखा जाता है जो मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए आधार प्रदान करता है। भावनाओं के बजाय विवेक को वरीयता दी जा रही है, और यह सभी प्रकार के बफर के स्थिर निर्माण में परिलक्षित होता है। एक व्यापक अर्थ में, यह दृष्टिकोण विदेशी मुद्रा भंडार के संचय में परिलक्षित होता है, और जैसा कि हमारे अनुभव से पता चलता है, वास्तव में वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के अभाव में यह भंडार हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा साधन बन गया है।

हमारे वित्तीय बाजारों और संस्थानों को वैश्विक स्पिलओवर के खतरे से बचाने के लिए साधन प्रदान करने के अलावा, इस भंडार ने बाहरी ताकत के आधार का निर्माण करने में मदद की है, जैसा कि मोडेस्ट एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग और डेट-जीडीपी अनुपात में परिलक्षित होता है। हमारा मानना है कि यह जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए और भारत की विकास रणनीति की वित्तपोषण आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन और साइबर खतरों जैसी नई चुनौतियों का प्रबंधन करने की हमारी क्षमता को मजबूत कर रहा है।

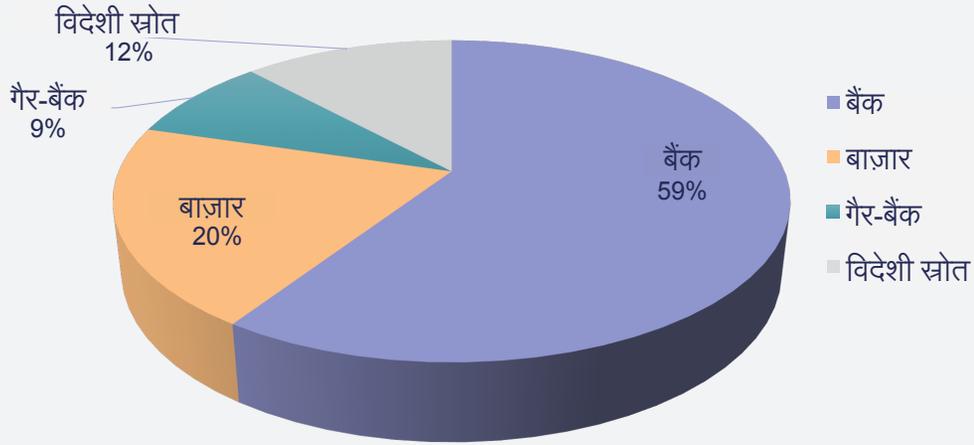
धन्यवाद।

अनुबंध 1

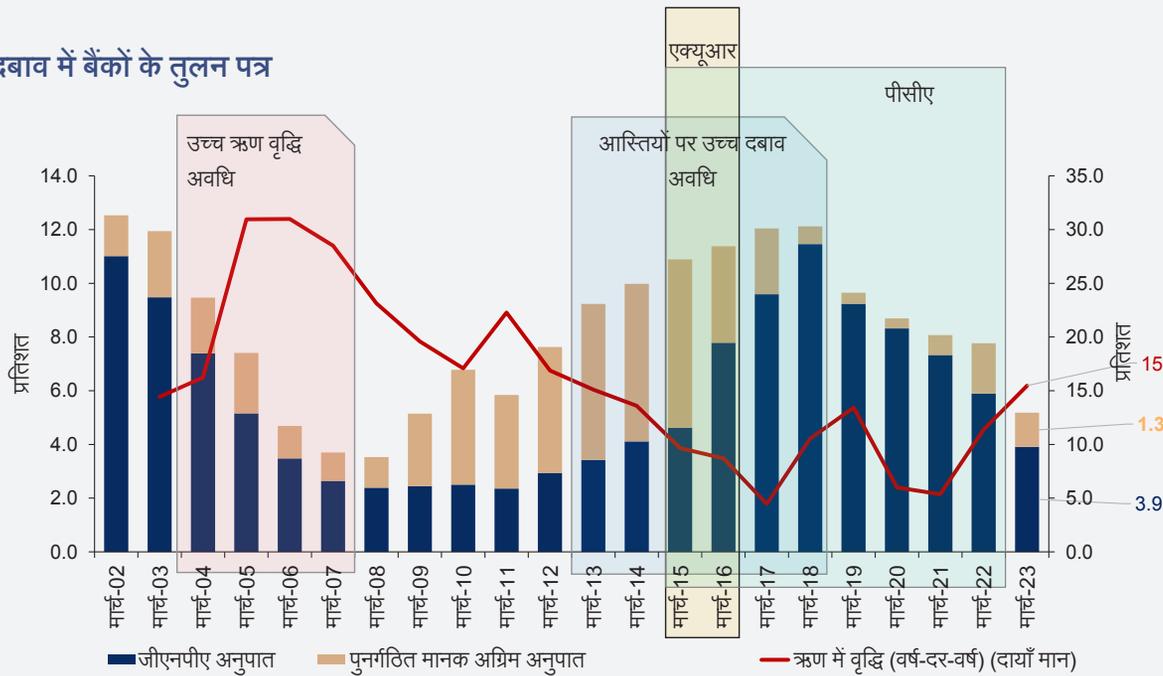
भारत का वित्तीय क्षेत्र – अधिकता से आघात-सहनीयता तक

भारतीय वित्तीय क्षेत्र की संरचना

भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह

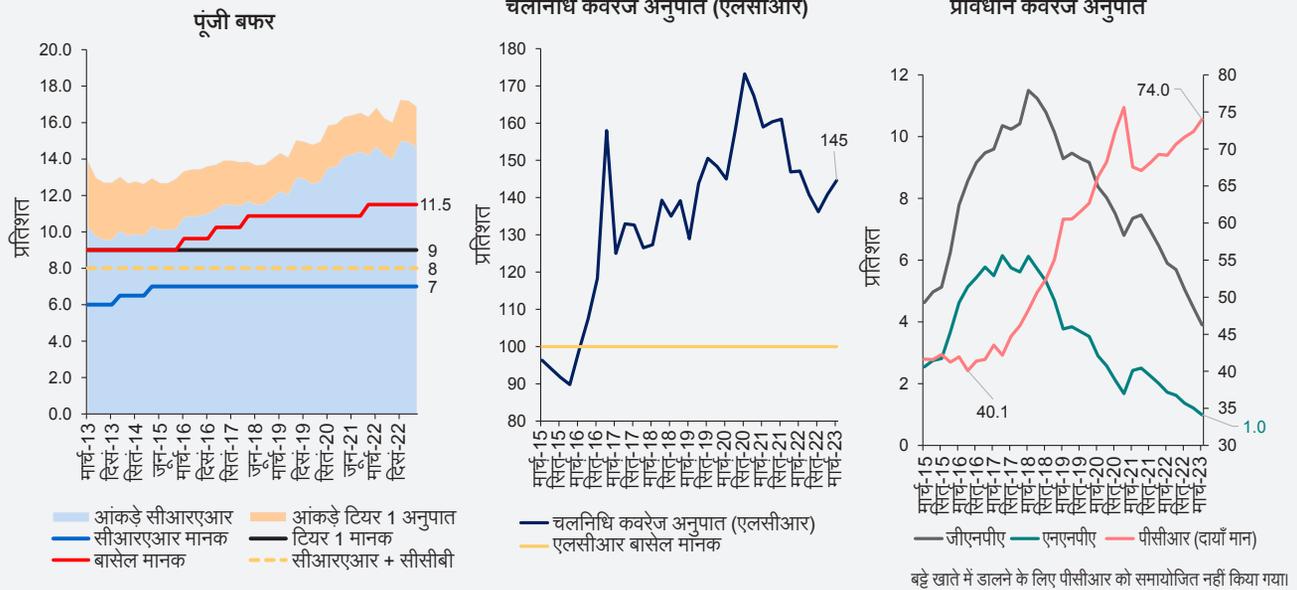


दबाव में बैंकों के तुलन पत्र

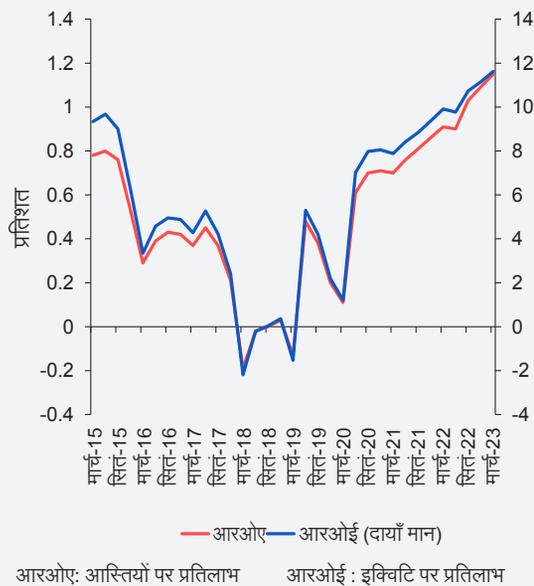


एक्यूआर: आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा पीसीए: त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

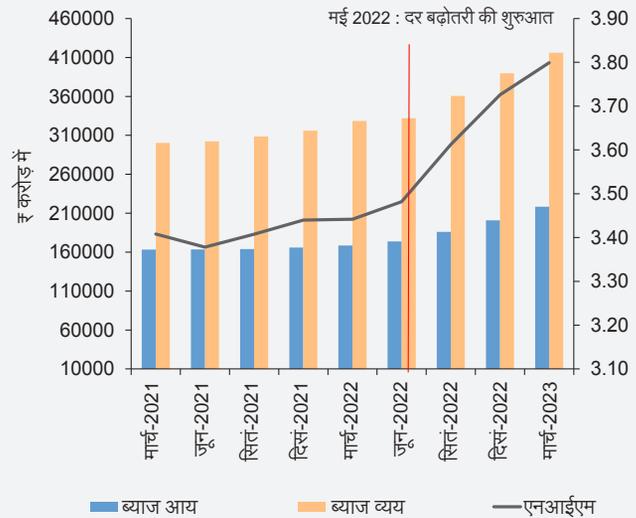
बफर का पुनर्निर्माण



लाभप्रदता पर प्रतिलाभ



बैंकों की निवल ब्याज आय



बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

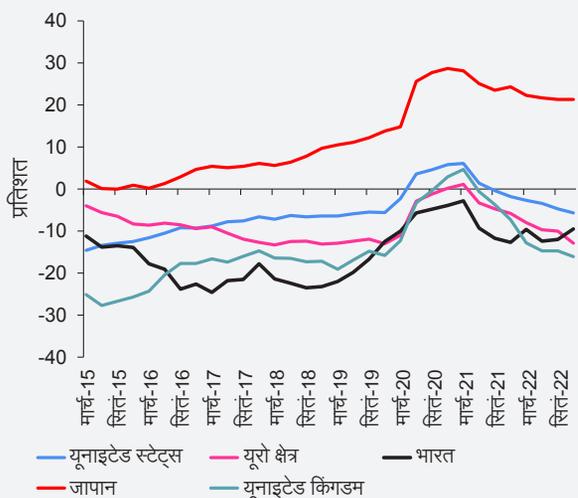
अवधि	रेपो दर (बीपीएस)	मीयादी जमा दरें (बीपीएस)			उधार दरें (बीपीएस)			
		डबल्यूएडीटीडीआर – नया जमा		डबल्यूएडीटीडीआर- बकाया जमा राशियाँ	ईबीएलआर	1-वर्षीय- एमसीएलआर (ओसत)	डबल्यूएएलआर- नया रुपया ऋण	डबल्यूएएलआर- बकाया रुपया ऋण
		खुदरा जमा	खुदरा और थोक जमा	खुदरा और थोक जमा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सहजता अवधि- फर 2019 से मार्च 2022	-250	-209	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्त अवधि- मई 2022 से जुलाई 2023	+250	173	232	152 (151)	250	155@	193	110 (112)
मेमो								
अप्रैल से जुलाई 2023	0	-1	-13	39 (38)	-	0	12	10 (12)
अप्रैल-2023	0	0	-12	12	-	0	-24	4
मई-2023	0	-3	-4	9	-	0	19	2
जून-2023	0	3	2	10	-	0	-7	4
जुलाई- 2023	0	-1	1	8 (7)	-	0	24	0 (2)

डबल्यूएएलआर: भारत ओसत उधार दर; डबल्यूएडीटीडीआर: भारत ओसत घरेलू मीयादी जमा दर; एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य बेचमार्क आधारित उधार दर; ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है। @: डेटा मई 2022 से अगस्त 2023 तक के लिए है।

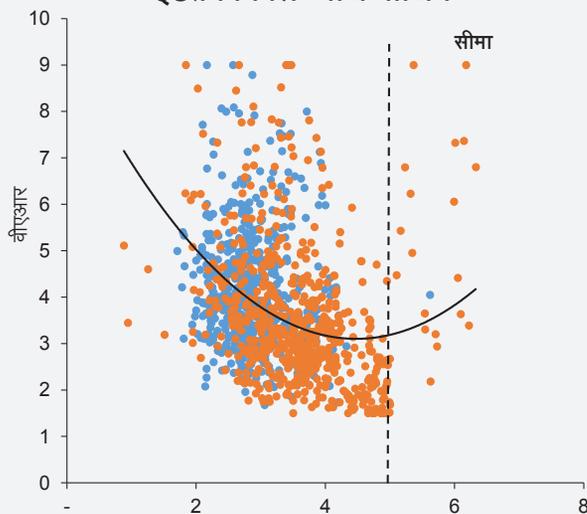
टिप्पणी: (i) कोष्ठक में डेटा एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाता है। (ii) जून 2023 के अंत तक कुल जमा राशियों में चालू और बचत जमा राशियों का हिस्सा 414 प्रतिशत (चालू खाता जमा: 9.6 प्रतिशत और बचत जमा: 31.8 प्रतिशत) था। बचत जमा में संचरण बहुत धीमा रहा है (मौजूदा सख्त अवधि में 5 बीपीएस), जो बैंकों की समग्र जमा लागत में संचरण को कम करता है।
स्रोत: आरबीआई।

अति-सक्रियता की जांच

ऋण और जीडीपी अंतराल

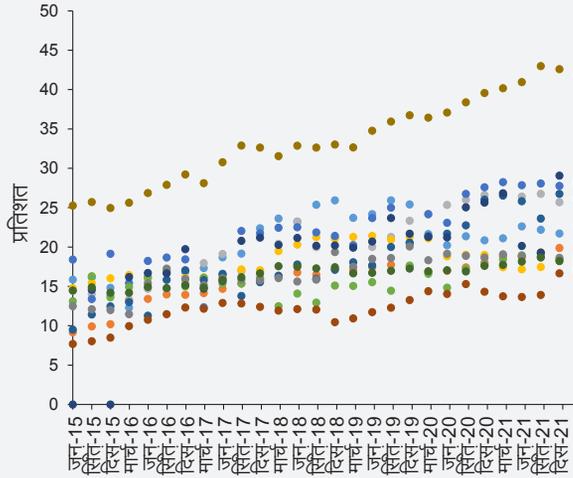


इष्टतम निवल ब्याज मार्जिन



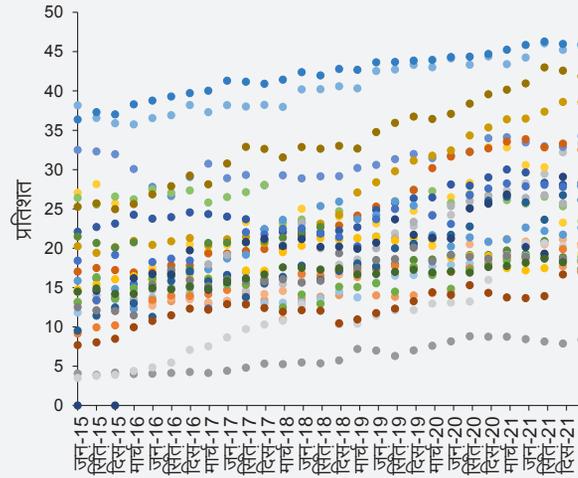
कुल ऋण में खुदरा ऋण का हिस्सा

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के कुल ऋण में खुदरा ऋण का हिस्सा



टिप्पणी: प्रत्येक बिंदु दर्शाई गई तिमाही के कुल ऋण में पीएसबी के खुदरा ऋण को दर्शाते हैं।

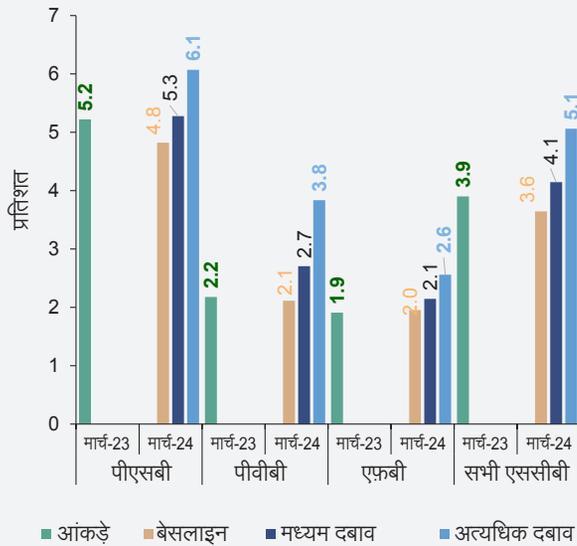
निजी क्षेत्र के कुल ऋणों में खुदरा ऋणों का हिस्सा



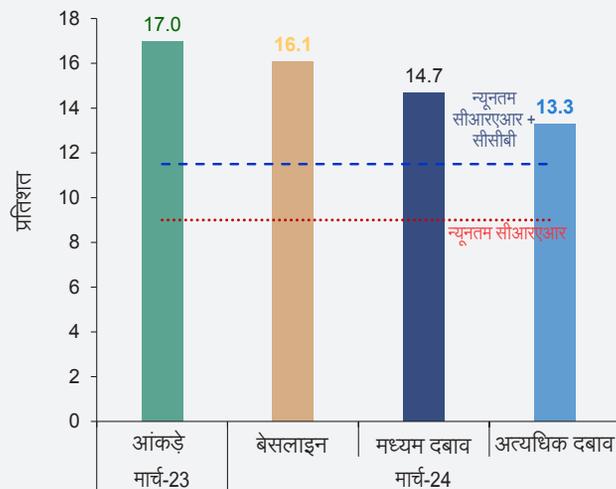
टिप्पणी: प्रत्येक बिंदु दर्शाई गई तिमाही के कुल ऋण में पीवीबी के खुदरा ऋण के हिस्से को दर्शाते हैं।

मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट (1/2)

जीएनपीए अनुपात अनुमान

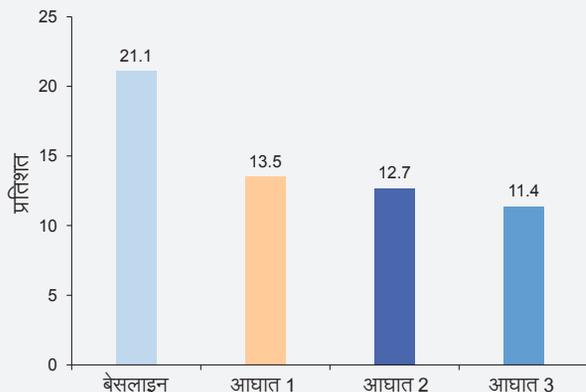


सीआरएआर अनुमान



मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट (1/2)

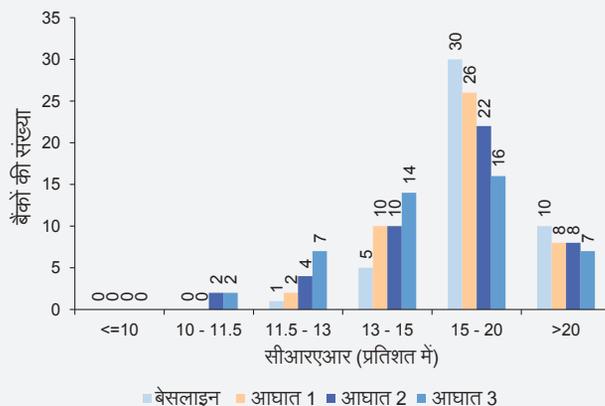
चलनिधि जोखिम – आघात और परिणाम



टिप्पणी: चलनिधि के आघातों में 75 प्रतिशत प्रतिबद्ध ऋण-व्यवस्था की मांग (स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा के साथ-साथ क्रेडिट प्रतिबद्धताओं के अप्रयुक्त हिस्से शामिल हैं) और नीचे दिए गए अनुसार गैर-बीमाकृत जमा के एक हिस्से की निकासी शामिल है:

आघात	आघात 1	आघात 2	आघात 3
गैर-बीमाकृत जमा का निकासी प्रतिशत	10	12	15

ऋण संकेंद्रण जोखिम: समूह उधारकर्ता – एक्सपोजर

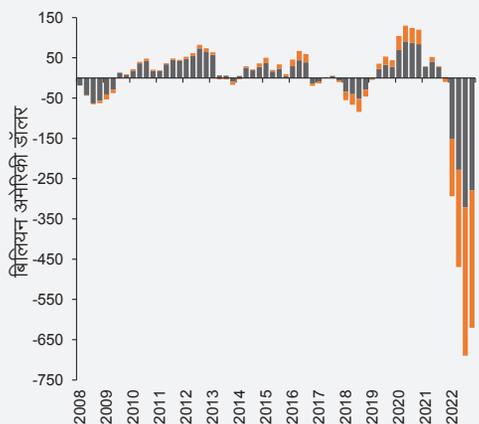


टिप्पणी: चुनिंदा 46 एससीबी के लिए व्यवस्था।

आघात 1: शीर्ष 1 समूह उधारकर्ता भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफला।
 आघात 2: शीर्ष 2 समूह उधारकर्ता भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफला।
 आघात 3: शीर्ष 3 समूह उधारकर्ता भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफला।

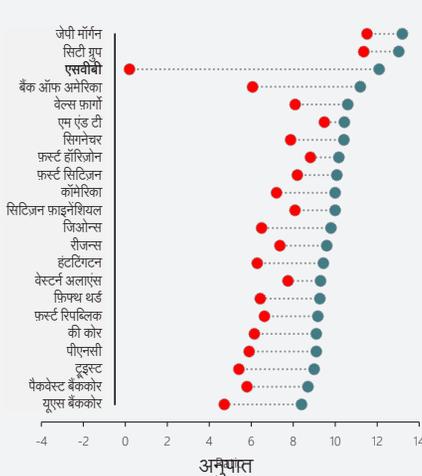
अप्राप्य हानि

एफएस और एचटीएम के तहत अप्राप्य हानि - अमेरिकी बैंक



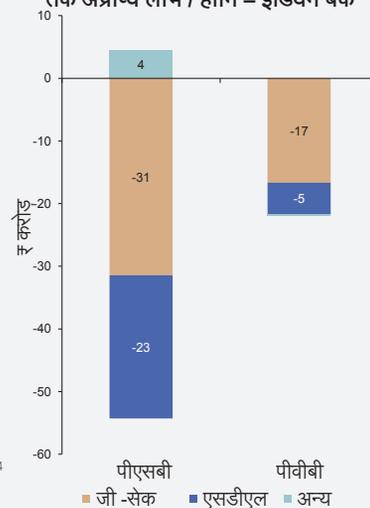
■ बिक्री प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध ■ परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियाँ

सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात पर अप्राप्य हानि का प्रभाव – अमेरिकी बैंक



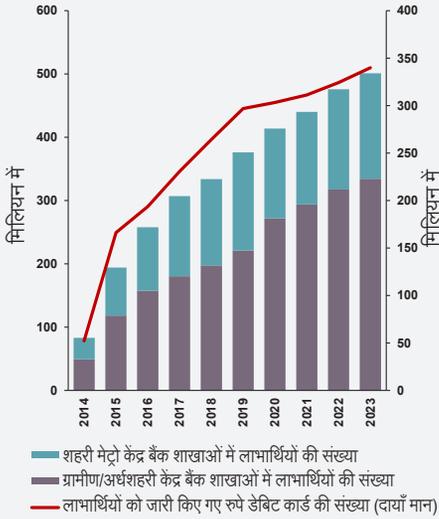
● अप्राप्य हानि के लिए सीईटी1 अनुपात समायोजित
 ● सीईटी1 अनुपात रिपोर्टेड

एचटीएम पोर्टफोलियो – 31 मार्च 2023 तक अप्राप्य लाभ / हानि – इंडियन बैंक

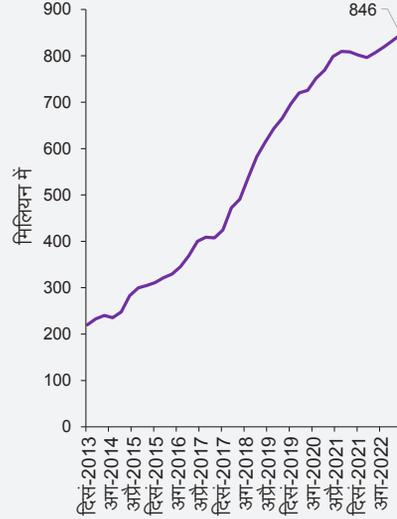


डिजिटल क्रांति के समर्थक - जैम ट्रिनिटी

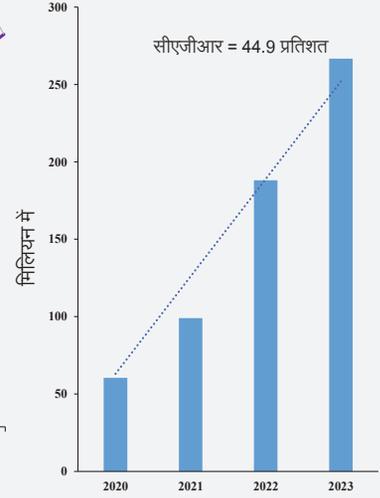
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत लाभार्थी



भारत में मोबाइल इंटरनेट ग्राहक

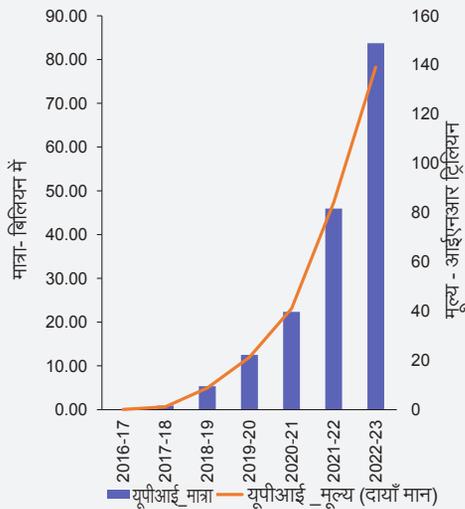


भुगतान अवसंरचना – यूपीआई क्यूआर

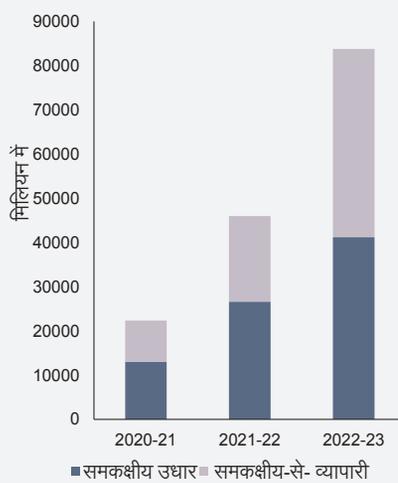


एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)

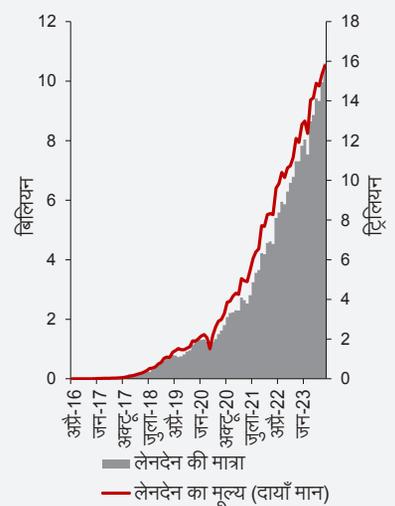
यूपीआई लेनदेन



यूपीआई के माध्यम से व्यापारिक लेनदेन का शेयर- मात्रा

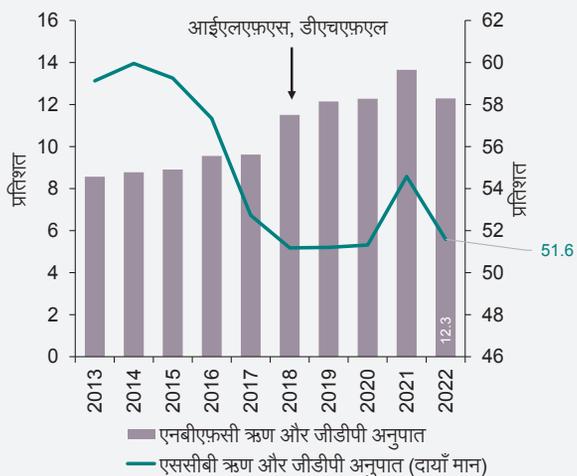


यूपीआई की वृद्धि

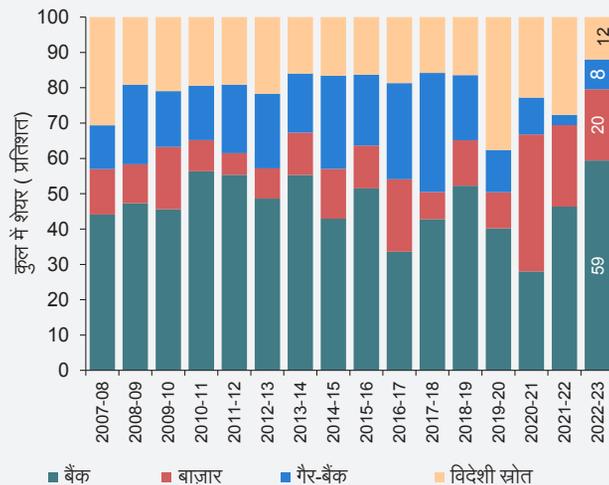


एनबीएफसी क्षेत्र (1/2)

एनबीएफसी एवं एससीबी ऋण और जीडीपी अनुपात



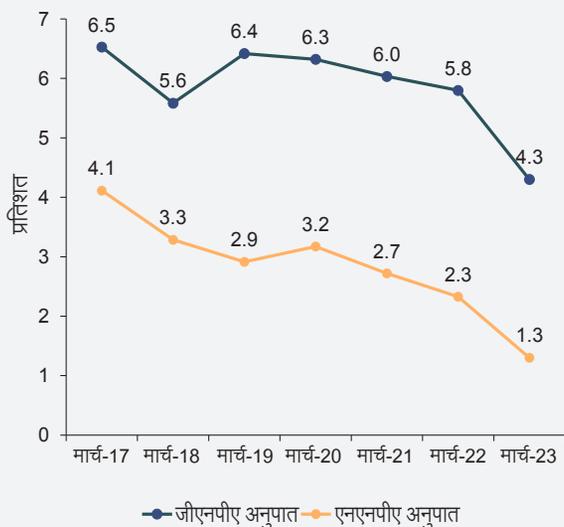
वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का प्रवाह



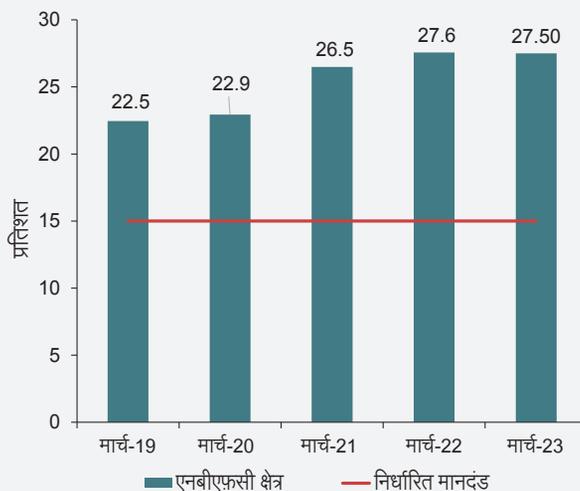
आईएलएफएस : इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस FHL: डीएचएफएल : दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता (2/2)

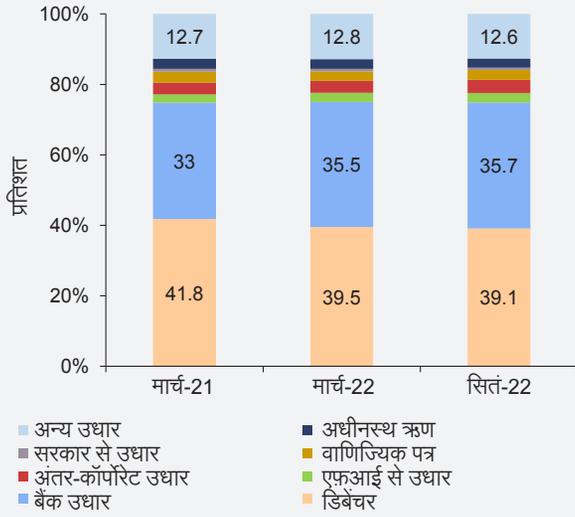
एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता



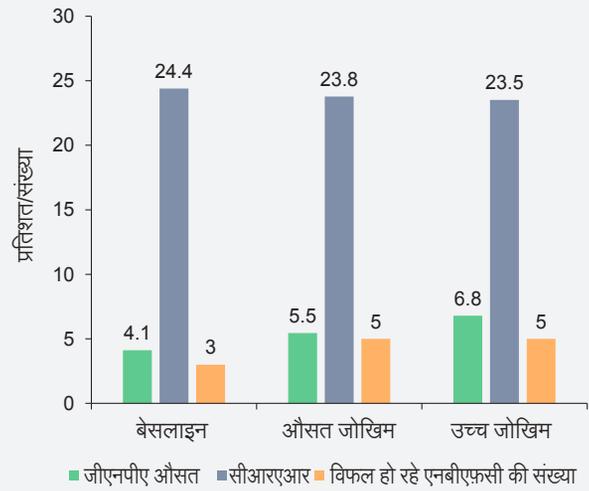
पूंजी पर्याप्तता



एनबीएफसी के निधि का स्रोत

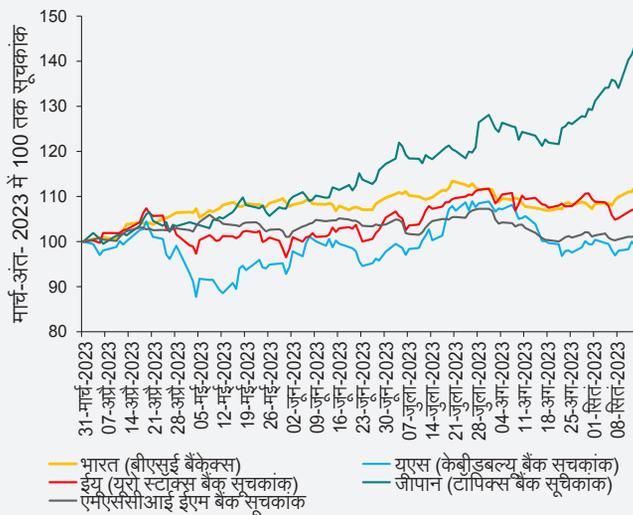


ऋण जोखिम दबाव परीक्षण – व्यवस्था स्तर

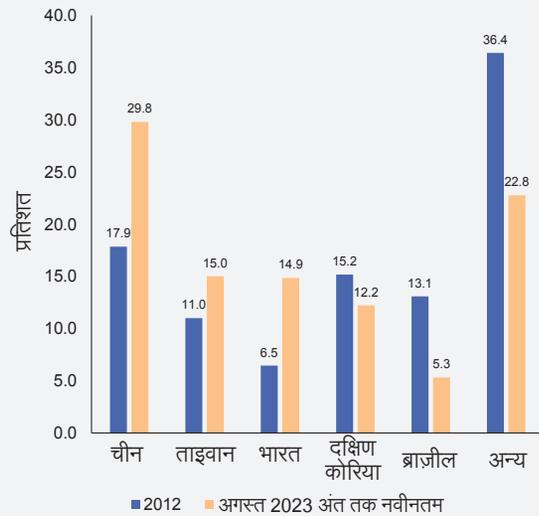


भारतीय इक्विटी बाजार और एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक

बैंकिंग सूचकांकों में स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव

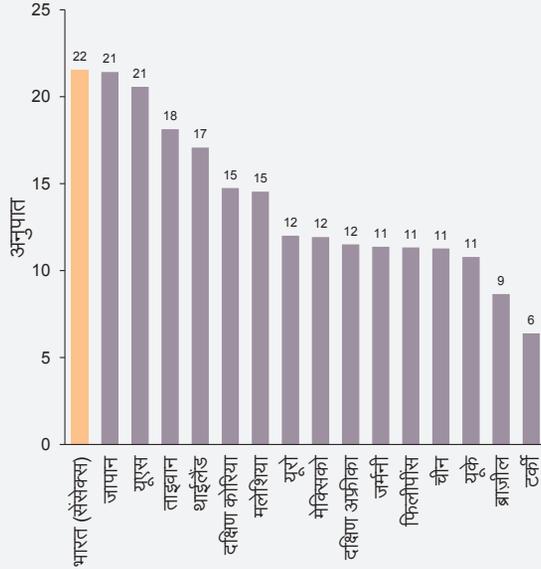


एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भार

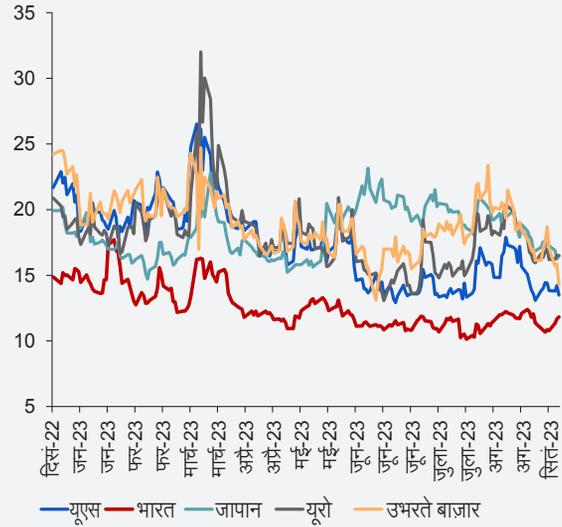


भारतीय इक्विटी बाजार - वित्तीय स्थिति

12-माह वायदा पीई गुणक



इक्विटी बाजार की अस्थिरता (वीआईएक्स)

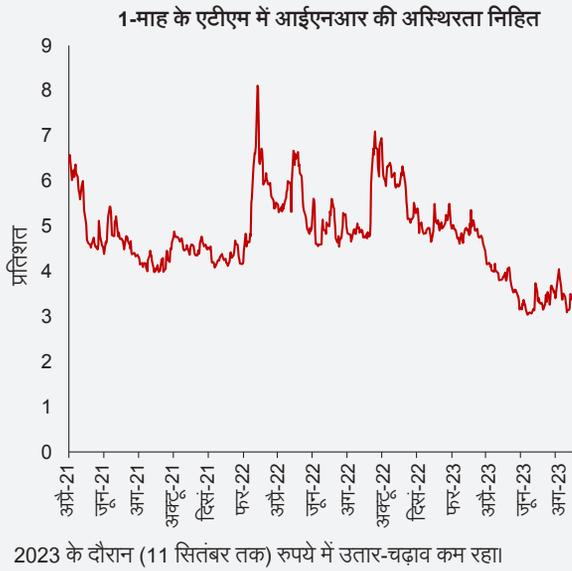


भारतीय बांड बाजार

भारत के जी-सेक प्रतिफल में उतार-चढ़ाव

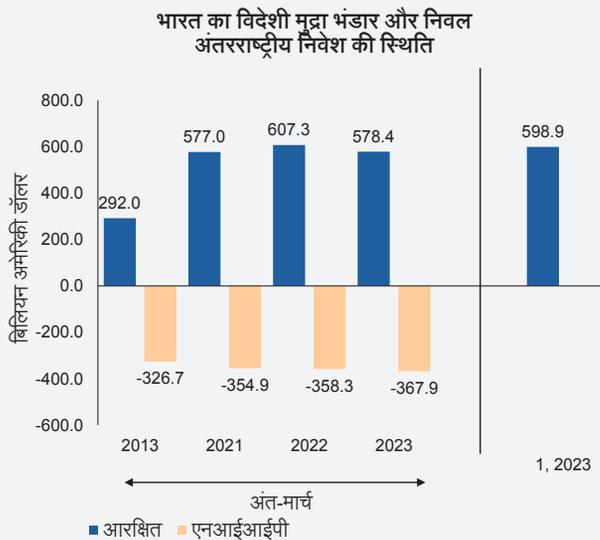


भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार



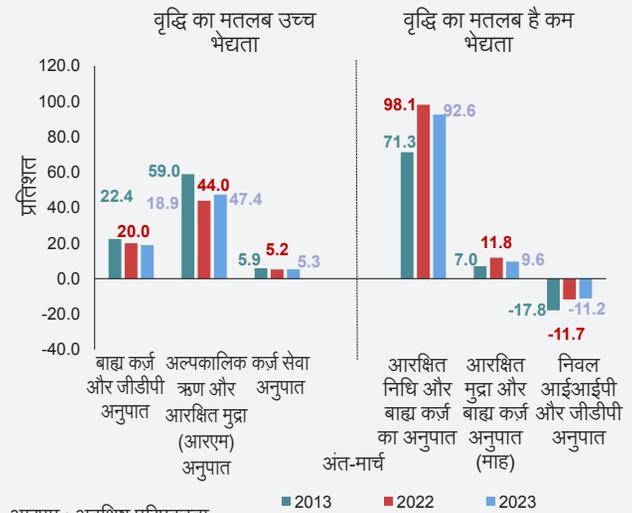
भिन्नता का गुणांक	
भारतीय रुपया	0.7 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3
यूरो	1.1 1.0 1.0 0.5 1.1 0.9 1.1 0.6
यूके पाउंड	1.3 0.8 1.4 0.4 0.8 1.0 1.0 0.4
जापानी येन	1.2 1.7 1.6 0.9 1.6 1.4 1.5 1.0
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर	1.6 1.5 0.8 0.8 1.3 1.3 1.0 1.0
कनाडाई डॉलर	0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.4 0.7
कोरियाई वॉन	1.3 2.3 0.7 0.9 0.7 1.2 1.1 1.1
न्यूजीलैंड डॉलर	1.3 1.4 0.8 1.0 1.7 1.0 1.1 1.2
सिंगापुर डॉलर	0.8 0.9 0.7 0.3 0.8 0.4 0.8 0.5
स्वीडिश क्रोना	1.1 0.8 1.3 0.7 2.3 0.8 2.4 1.3
स्विस फ्रैंक	0.6 0.9 1.1 0.8 0.8 0.7 1.6 0.4
हॉंगकांग डॉलर	0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
अर्जेंटाइन पेसो	1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0 10.3
ब्राज़िली रियाल	2.3 1.1 1.1 1.1 0.8 1.4 1.2 1.1
चीनी युआन	0.8 1.0 0.5 0.3 1.0 0.7 0.5 0.6
चिली पेसो	2.3 1.8 1.3 1.0 1.0 0.7 1.4 1.0
इंडोनेशियाई रुपिया	1.8 0.7 0.9 0.5 0.8 0.4 0.4 0.4
मलेशियाई रिंगीत	1.3 1.8 0.8 0.5 1.4 0.7 1.3 0.9
मेक्सिकन पेसो	1.3 1.3 1.8 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9
फिलिपीनी पेसो	0.9 0.9 0.7 1.1 0.6 0.6 0.8 0.9
रूसी रुबल	2.4 2.5 1.2 1.4 1.8 2.4 0.9 1.9
दक्षिण अफ्रीकी रैंड	1.0 2.2 1.2 0.9 2.7 2.2 2.6 1.3
थाईलैंड की मुद्रा	1.7 2.0 0.9 0.5 1.1 0.9 1.1 0.8
तुर्की लीरा	0.2 0.1 0.5 0.5 1.7 7.1 1.6 1.1
वियतनामी डॉन्ग	0.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
माह	जन-23 फर-23 मार्च-23 अप्रै-23 मई-23 जून-23 जुला-23 अग-23

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार - राष्ट्रीय सुरक्षा जाल



• 1 सितंबर 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 598.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
 • इसके अलावा, मार्च 2023 के अंत में आईआईपी और जीडीपी अनुपात घटकर (-) 11.2 प्रतिशत हो गया।
 • भारत का बाह्य कर्ज और जीडीपी अनुपात कई प्रमुख ईएमई से कम है और विदेशी ऋण और आयात का आरक्षित कवर अधिकांश प्रमुख ईएमई की तुलना में अधिक है।

भारत के बाह्य भेद्यता संकेतक



आरएम : अवशिष्ट परिपक्वता